(क) कितने भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्ड बनाते समय राज्य सभा के भतपूर्व संसद सदस्यों से अधिक राशि वसूल की जाती है जबकि लोक सभा के भूतपूर्व संसद सदस्यों से कम राशि ली जाती है ; यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का दोनों सभाओं के भूतपूर्व संसद सदस्यों से एक समान राशि लेने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं पाने वाले भूतपूर्व संसद सदस्यों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त कर रहे संसद सदस्यों समेत पेंशन भोगियों के बारे में सूचना श्रेणीवार नहीं रखी जाती है । चूंकि भूतपूर्व संसद सदस्य भी वे सुविधाएं पाने के हकदार हैं जो मौजूदा संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त की जा रही हैं, इसलिए लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय वर्तमान संसद सदस्यों से जो निम्नलिखित अंशदान वसूल करती है वही अंशदान यह मंत्रालय भूतपूर्व संसद सदस्यों से भी वसूल कर रहा है :—

भूतपूर्व संसद सदस्य, लोक सभा 2.50 रुपये प्रतिमास

भूतपूर्व संसद सदस्य राज्य सभा 4 रुपये प्रतिमास

तथापि संसदीय कार्य मंत्रालय से वर्तमान संसद सदस्यों से समान अंशदान वसूल करने का अनुरोध किया गया है ।

Conversion of Tinsukia station as Model Railway Station

1695. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision for converting Tinsukia Railway Station into a Model Railway Station; and

(b) if so, what is the total amount earmarked for this scheme, and by when the scheme is going to be implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) About Rs. 190.00 lakhs are likely to be spent on conversion of Tinsukia Station into a Model Station The scheme is likely to be completed by March, 1991, subject to availability of funds.

Problems faced by Public Sector Undertakings for transportation by Railways

1696. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the public sector enterprises like Messers Oil India, ONGC, Fertilizer Corporation of India, Coal India and major tea gardens earning valuable foreign exchange for the country have been facing acute problem in transportation of their finished products and raw materials, heavy machinery and equipment from ports and other major cities of India to their plants and *vice-versa* mainly due to single line metre gauge railway track in the areas of the above units; and

(b) if so, whether the Government propose to take up the extension works of broad gauge railway line from Guwahati to Upper Assam in view of national interest?